

**भारत सरकार**  
**श्रम और रोजगार मंत्रालय**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या- 2306**  
**सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक)**

**रोजगार सृजन संबंधी योजनाओं की समीक्षा**

**2306. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल:**

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने विगत दस वर्षों के दौरान प्रमुख राष्ट्रीय योजनाओं के अंतर्गत रोजगार सृजन की नियमित रूप से समीक्षा की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा और प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं;
- (ग) देश में विगत दस वर्षों के दौरान राजस्थान सहित राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है; और
- (घ) क्या यह सच है कि विभिन्न आर्थिक सुधारों के बावजूद देश में बेरोजगारी की दर अपेक्षाकृत उच्च स्तर पर है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

**उत्तर**  
**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**  
**(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)**

(क) से (घ) नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, सरकार विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का व्यौरा [https://dge.gov.in/dge/schemes\\_programmes](https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes) पर देखा जा सकता है।

सरकार प्रत्येक वित्त आयोग के अवधि शुरू होने से पहले सभी योजनाओं और कार्यक्रमों की सुनियोजित समीक्षा और मूल्यांकन करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे लगातार प्रासंगिक, प्रभावी रहें और बदलती प्राथमिकताओं के साथ तालमेल बिठा सकें।

रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा स्रोत आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) है, जो 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किया जाता है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर), जो 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति पर रोजगार को दर्शाता है, वर्ष 2017-18 में 46.8% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 58.2% हो गया है।

इसके अलावा, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 2017-18 में 6.0% से घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई है।

पीएलएफएस रिपोर्ट में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विस्तृत जानकारी उपलब्ध है, जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट <https://www.mospi.gov.in/publications-reports> पर देखा जा सकता है।

\* \* \* \*